मॉं
जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझाए
दिए से मेरी मां, मेरे लिए काजल बनाती है
-मुनव्वर राना

लोकमत समाचार
नागपुर, रविवार, 10 मई 2015

लोकमत समाचार

तमसो मा ज्योतिर्गमय

हर एक कठिनाई जिससे आप मुंह मोड़ लेते हैं, एक भूत बन कर आपकी नींद में बाधा डालेगी. ■ **रवींद्रनाथ टैगोर**

संपादकीय

अपने हालात को पहचाने पाकिस्तान

पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं. आए दिन कोई न कोई बड़ा हमला कर आतंकवादी पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराते रहते हैं. बावजूद इसके पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने में हमेशा उदासीन ही नजर आया है. आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है यह तो वही बता सकता है, लेकिन आतंकवादियों के प्रति उसका रवैया हमेशा से ही नरम रहा है. आतंकवाद से लड़ने के बजाय पड़ोसी देश में कैसे अशांति बनी रहे इसमें उसकी अधिक दिलचस्पी देखी गई है. आखिर पाकिस्तान अपने हालात को क्यों नहीं पहचान पा रहा है या यह उसकी कूटनीति का कहीं कोई हिस्सा तो नहीं है? ऐसे अनेक सवाल अनुत्तरित हैं. शुक्रवार की घटना में पाकिस्तानी सेना के एक हेलिकॉप्टर को आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान-ए-पाकिस्तान (टीटीपी) द्वारा मार गिराए जाने के बावजूद पाकिस्तान इसे महज एक दुर्घटना मान रहा है. इतने बड़े हमले के बाद भी, जिसमें दो राजदूतों समेत 7 लोगों की मौत हो गई, पाकिस्तान का किसी भी आतंकवादी या विध्वंसक गतिविधि की संभावना से इनकार करना आतंकवादियों के प्रति उसके नरम रवैये को ही परिलक्षित करता है. पाकिस्तानी सेना के इस एमआई-17 हेलिकॉप्टर में 11 विदेशी समेत 6 पाकिस्तानी नागरिक भी सवार थे. यह हमला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के गिलगित-बाल्टिस्तान प्रशासनिक क्षेत्र में उस समय हुआ जब सभी राजनयिक एक परियोजना की शुरुआत के सिलसिले में गिलगित-बाल्टिस्तान जा रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नवाज शरीफ समारोह को संबोधित करने वाले थे. तालिबानी दावे पर गौर करें तो दरअसल निशाने पर नवाज शरीफ ही थे, लेकिन दूसरे हेलिकॉप्टर में होने से वे सुरक्षित बच गए. एक तरफ तालिबानी प्रवक्ता ई-मेल भेजकर एक विमानभेदी प्रक्षेपास्त्र की मदद से हेलिकॉप्टर गिराने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सेना के प्रवक्ता इसे तकनीकी खराबी के कारण होने वाली दुर्घटना बता रहे हैं. हालांकि इस हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इनक्वायरी का गठन कर दिया गया है, लेकिन जब सेना के प्रवक्ता ही तालिबानी हमले का पुरजोर खंडन कर रहे हैं तो जांच के नतीजे का अनुमान लगाया जा सकता है. इसके पहले भी पिछले साल दिसंबर में पेशावर के एक आर्मी स्कूल पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें शिक्षक और मासूम बच्चे मारे गए थे. छिटपुट घटनाएं तो होती ही रहती हैं जिसे देखने का पाकिस्तान का नजरिया ही बिल्कुल अलग है. कई खूंखार आतंकवादी सरगना वहां पनाह लिए हैं, फिर भी वहां की सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की नहीं सूझती. कहीं न कहीं उन तत्वों को परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन ही माना जाएगा. सीमा पार से फायरिंग का मामला हो या घुसपैठ, पाकिस्तानी शह के बिना कतई संभव नहीं हो सकता है. भले ही पाकिस्तान इन आरोपों का खंडन करता रहे, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं जिससे उनके समर्थन का पता चलता है. अब स्वयं पाकिस्तान भी उन आतंकवादियों के लपेटे में है. अतः उसे आतंकवादियों से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए. सिर्फ पड़ोसी देश में अशांति फैलाने के उद्देश्य से यदि उन्हें पनाह दी जा रही है तो स्वयं वह भी कब तक महफूज रह सकता है. दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले भी गड्ढे में गिरने से नहीं बच सकते यह कहावत भी उसके लिए चरितार्थ हो रही है. आतंकवाद की जड़ों को खत्म करना पाकिस्तान सरकार की पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे वह बार-बार नजरंदाज करती रही है. ■■

भावना

लघुकथा

राजिंदर बिमल

जिस जगह मां मरी थी, वहां रात को तीनों बेटियों ने रेत की एक ढेरी लगाकर तसला उल्टा रख दिया था ताकि सुबह देख सकें कि मां अपने अगले जन्म में किस जून में गई हैं.

अगले दिन तसला उठाया गया. बेटियों को लगा जैसे ढेरी और ऊंची हो गई है.

''मंदिर लगता है! लगता है जैसे किसी अच्छी जगह गई है.'' बड़ी बोली, छोटी भी उससे सहमत थी.

पास खड़ी दोनों बहुएं दूर जाकर खुसर-फुसर करने लगीं, ''बलखाती लकीर तो साफ नजर आ रही है, जरूर सांप बनी होगी अगले जन्म में, सांप.'' ■■

दिखने लगे राजनीतिक दांत

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

कान्हा या रणथंभौर के जंगल में शेरनी के नवजात बच्चे कुछ महीनों में ही तेजी से उछलने-कूदने लगते हैं. शेरनी या शेर उनके पीछे भागकर नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो वे छोटा सा मुंह खोल दांत निकालकर तेजी से भागते हैं. राजनीति में भी थोड़ी चुनावी सफलता और दूरगामी लक्ष्य रखने वाले सांसद उचित अवसर पर दांत दिखाने लगते हैं. इतिहास भरा पड़ा है. जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, फिरोज गांधी, चंद्रशेखर, कृष्णकांत, मोहन धारिया, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये, जार्ज फर्नांडीस, ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी जैसे पचीसों नाम गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने युवा काल में सत्तारूढ़ ही नहीं अपनी पार्टी के नेतृत्व को भी ललकारा. पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीति में अपनी ही पार्टी में राजनीतिक दांत दिखा सकने वाले बहुत कम हो गए थे. जनवरी 2014 के चुनावी अभियान से सत्ताकाल के 11 महीने पूरे होने तक भाजपा की संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सरकार की विफलता, मंत्रियों के निकम्मेपन की आवाज हाल ही में उठना सचमुच धारदार दांतों का प्रदर्शन है. युवा तुर्क कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के निर्वाचन क्षेत्र बलिया से लोकसभा चुनाव में विजयी रहे भरत सिंह ने संसदीय दल की बैठक में निर्भयतापूर्वक प्रधानमंत्री और पार्टी की गलतफहमियां दूर कर आईना दिखाने का प्रयास किया, तो कई भाजपा सांसदों ने मेजें थपथपाकर और कुछ ने खड़े होकर समर्थन किया. अब तक संसद के गलियारों और सांसदों के घरों-होटलों में भोजन के अवसरों पर उनका दुःख-दर्द सुनने को मिलता था. भाजपा कार्यकर्ता या संघ के स्वयंसेवक ही नहीं सांसदों को भी उनके सामान्य निवेदनों पर मंत्रियों से अनुकूल उत्तर न मिले और जनहित के काम भी अटके रहें या विभिन्न मंत्रालयों की समितियों में अवैतनिक नामांकन तक लटका रहे, तो सांसद अपने क्षेत्र और समर्थकों को क्या मुंह दिखाए? पराकाष्ठा यह हो कि मंत्री या पार्टी अध्यक्ष तक मिलने का समय न दें, तब निराशा, खीझ और गुस्से में दांत बाहर निकलेंगे ही.

भाजपा सांसदों की नाराजगी इसलिए भी स्वाभाविक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा समय-समय पर ली जाने वाली बैठकों में सांसदों को सरकार की एकवर्षीय सफलता का ढोल गांव-गांव जाकर पीटने की सलाह दी जाती है. इन बैठकों को सांसदों की 'क्लास' लेना कहा जाता है, क्योंकि वेंकैया नायडू बैठक में संसद सत्र के दौरान किसी की अनुपस्थिति पर स्कूली बच्चों की तरह सांसदों को खड़ा करके जवाब मांगते हैं. दो बड़े नेता आंखों से घूरते हैं और फिर भविष्य में लापरवाही न करने की हिदायत देकर बैठ जाते हैं. अब सांसद खुद पूछना चाहते हैं कि विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के मुद्दे पर वे जनता को क्या बताएं? कोयला खदानों की नीलामी से दो लाख करोड़ रु. खजाने में आने की मोदी-जेटली-शाह की सार्वजनिक घोषणाओं को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्यप्रदेश में कैसे दोहराएं क्योंकि अभी तो केवल सात हजार करोड़ एडवांस हुआ है और दो लाख करोड़ इन राज्यों में तीस साल में पहुंचेंगे. तब तक कितने सांसद पुनः संसद में पहुंचेंगे और कितने जीवित भी रहेंगे? शीर्ष नेता साल में 3690 किलोमीटर सड़क बनाए जाने की उपलब्धि गिनाने की सलाह देते हैं, तो भरत सिंह जैसे सांसद कहते हैं कि 'हमारे इलाके में तीन किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, फिर हम साढ़े तीन हजार किलोमीटर का दावा किस मुंह से जनता के सामने करें? सलाह दी गई है कि देश में पहली बार एक लाख करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होने की रोशनी जनता को दिखाएं, तब सांसद कहते हैं कि 'रामलीला की भूमि अयोध्या और कृष्ण कन्हैया के बाद हेमामालिनी के क्षेत्र मथुरा-वृंदावन में 8-10 घंटे बिजली गायब रहने के बाद कौन सा चिराग दिखाकर जनता को मूर्ख बनाएं?' स्वच्छ भारत अभियान में भाजपा शासित दिल्ली-मुंबई जैसे नगर निगमों-महापालिका की सड़कों पर गंदगी के ढेर रहने के बाद केवल टी.वी. विज्ञापनों के जरिए लोगों को कैसे संतुष्ट करें? न पर्याप्त कूड़ाघर हैं, न ही कर्मचारी, न ही अमेरिका की तरह कूड़ा पहुंचाने वाले वाहन और न ही कूड़ा नष्ट करने वाले ठिकानों का प्रबंध है. गंगा की सफाई के लिए दो हजार करोड़ रुपया बजट में रखा, लेकिन नौकरशाही और ठेका आवंटन के चक्कर में दो हजार रुपए भी खर्च नहीं हुए. जब वाराणसी की गंगा और दिल्ली की यमुना से दो ट्रक तक गंदगी साफ नहीं की जा सकी, तो नर्मदा, क्षिप्रा, कावेरी नदियों की सफाई के सपने कितने जन्म में पूरे होंगे?

पिछले कुछ वर्षों के दौरान राजनीति में अपनी ही पार्टी में राजनीतिक दांत दिखा सकने वाले बहुत कम हो गए थे. जनवरी 2014 के चुनावी अभियान से सत्ताकाल के 11 महीने पूरे होने तक भाजपा की संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरकार की विफलता, मंत्रियों के निकम्मेपन की आवाज हाल ही में उठना सचमुच धारदार दांतों का प्रदर्शन है.

जब भाजपा सांसदों के दांत निकल सकते हैं, तो चुनावी संघर्ष में घायल राजनेता दस महीनों की मरहम पट्टी के बाद मुंह धोकर दांत दिखाने से कैसे चूकेंगे? कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में कितने ही सवाल 2014 से अब तक भाजपा नेतृत्व उछालता रहा. दस साल संसद में रहने के बावजूद 'नवजात' समझे जाने वाले राहुल गांधी ने एक महीने में गुर्राकर जवाब देना शुरू कर दिया. सत्ता के रथ को रोकने के लिए कमजोर समझे जाने वाले किसी विरोधी सेनापति का बिगुल बजाना नए संघर्ष की चुनौती से कम नहीं है. नेहरू, लालबहादुर शास्त्री, इंदिरा, राजीव, इंद्र कुमार गुजराल, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह तक किसी प्रधानमंत्री ने प्रतिपक्ष के नेताओं के परिजनों और व्यक्तित्व पर हल्की घटिया टिप्पणियां सार्वजनिक भाषणों में नहीं कीं. गंभीर राजनीतिक टकराव के बावजूद पारस्परिक सम्मान का संस्कार निभाया. जयप्रकाश नारायण को जेल तक जाना पड़ा, लेकिन अंदर या बाहर आने के बाद भी वह इंदिरा गांधी को 'इंदु बेटी' ही पुकारते रहे. चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को भी जेल भेजने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब वह उनके तुगलक रोड स्थित निवास पर पहुंचीं, तो चौधरी साहब ने प्रिय अतिथि की तरह सम्मान के साथ खातिर की. बाद में उनके समर्थन से प्रधानमंत्री पद पाया और खोया भी, लेकिन सार्वजनिक अवसरों पर राजीव-सोनिया के विरुद्ध कभी अशोभनीय टिप्पणियां नहीं कीं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा में पहुंचे कुछ बड़े नेताओं के संस्कार सत्ता के दलदल में क्यों इतने गड़बड़ा गए?

इसी का नतीजा है कि राहुल ब्रिगेड अब 'सूट बूट की सरकार, फॉरेन फ्लाइंग पीएम, पांच-सात अमीरों के रखवाले प्रधानमंत्री : जैसे जुमलों से नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमले बोल रही है. विदेश से काले धन को लाकर 15 लाख रु. हर हिंदुस्तानी के खाते में जमा कराने के वायदे की बार-बार याद दिला रहे हैं. रही सही कसर भूमि अधिग्रहण के नए कानून के प्रस्ताव ने पूरी कर दी. कांग्रेस, जनता दल (यू), समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टियों को जैसे 'अमृत कलश' मिल गया. सरकार के मुंह पर 'किसान विरोधी' मोटी कालिख पुत गई, जिसे धोने में भाजपा सांसद या अन्य प्रादेशिक नेता भी अपने को समर्थ नहीं समझ पा रहे हैं. लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मात्र किसी सरकार की सफलता की कुंजी नहीं है. संसद के उच्च सदन राज्यसभा, न्यायपालिका, राष्ट्रपति के रहते कोई पार्टी और सरकार मनमानी नहीं कर सकती. संविधान निर्माताओं ने निरंकुश सत्ता की मनमानी रोकने के लिए ही संविधान में समुचित प्रावधान किए हैं. प्रतिपक्ष को निरंतर चुनौती देने से अब सरकार राज्यसभा में बार-बार पिट रही है. न्यायपालिका को काबू में लाने के लिए किए गए नए प्रावधानों से सर्वोच्च अदालत ने तीखे तेवर अपना लिए हैं. दांत कई बार खुशी के अवसर पर हंसते हुए अच्छे लग सकते हैं, लेकिन संघर्ष के समय जवानी वाले दांत जहरीले साबित हो सकते हैं. ■■

सिपाही विद्रोह का वह शुभ दिन!

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लिहाज से दस मई एक अत्यंत महत्वपूर्ण तारीख है. 1857 में अंग्रेजों की सेना के देसी सिपाहियों ने राजधानी दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर स्थित मेरठ छावनी में इसी दिन गुलामी से मुक्ति के लिए पहला सशस्त्र अभियान शुरू किया था. उस गुलामी से, जो एक शताब्दी पहले 1757 में प्लासी की ऐतिहासिक लड़ाई में राबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की जीत के बाद से देश की छाती पर मूंग दलती आ रही थी.

आज की तरह उस दस मई को भी रविवार था. गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार के बाद से ही न सिर्फ निर्मम कोर्ट मार्शल, बल्कि गंभीर मानमर्दन झेल रहे अपने 85 साथियों को जेल तोड़कर छुड़ाने, इसमें बाधक बने अंग्रेज अफसरों को मारने और उनके बंगले फूंकने के बाद ये देसी सिपाही अपनी जीत का बिगुल बजाते हुए अगले दिन दिल्ली आ पहुंचे थे. फिर तो अपदस्थ सम्राट बहादुरशाह जफर को फिर से गद्दी पर बैठाए जाने के बाद यह अभियान देश के बड़े हिस्से में फैल गया था. कुछ इस तरह कि अंग्रेज अगले दो साल तक पश्चिम में पंजाब, सिंध व बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में अरुणाचल व मणिपुर और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल व कर्नाटक तक, अलबत्ता अलग-अलग वक्त पर खुले अलग-अलग मोर्चों पर, कभी मुंह की खाते और कभी छल प्रपंच से बढ़त हासिल करते रहे. उन्हें मैदानी इलाकों में हल जोतने वालों से लेकर छोटा नागपुर/रांची की पर्वतीय जनजातियों, हिंदुओं से लेकर मुसलमानों, सिखों, जाटों, मराठों व बंगालियों, शिक्षितों से लेकर अंगूठाछाप किसानों व मजदूरों, सिपाहियों से लेकर राजमिस्त्रियों, राजे-रजवाड़ों से लेकर मेहतरों और रानियों-बेगमों से लेकर उनकी दासियों-बांदियों तक के दुर्निवार क्रोध से निपटना पड़ा.

लेकिन शुरुआती सफलताओं और व्यापक जनभागीदारी के बावजूद, कई खोटों के कारण, यह अभियान अंग्रेजों की कुटिलताओं से पार नहीं पा सका. इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत तो किया लेकिन देश की ब्रिटिश उपनिवेश वाली नियति नहीं बदल सका. गौरांग महाप्रभुओं ने इसका दमन कर 90 सालों बाद तक अपनी सत्ता बनाए रखी और उसके सहारे इसके नायकों को खलनायक सिद्ध करने के बहुविध षड्यंत्र करते रहे. उनके षड्यंत्रों का सबसे बड़ा कुफल यह हुआ कि आधी शताब्दी तक इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में पहचाना ही नहीं गया और 'सिपाही विद्रोह' अथवा 'गदर' ही कहा जाता रहा. भले ही कार्ल मार्क्स ने उन्हीं दिनों 'ट्रिब्यून' में अपनी टिप्पणियों में लिखा था कि यह सैनिक बगावत न होकर भारतवासियों का राष्ट्रीय विद्रोह है और सैनिक उसे रूप देने के माध्यम भर हैं.

आज, जब 1857 के डेढ़ सौ साल पूरे होने के अवसर पर हुए रस्मी आयोजन भी पुराने पड़ गए हैं, जरूरत है कि उस दस मई की यादों को धुंधलाने न दिया जाए.

पचास साल तक एक विफल स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होने का खामियाजा चुकाती और अपने दुर्भाग्य पर रोती रही 10 मई के अच्छे दिन 1907 में आए, जब विजयोन्माद में अंधे अंग्रेज इस संग्राम और इसके नायकों पर तमाम लानतें भेजते हुए इंग्लैंड में जश्न मनाने पर उतरे. तब विनायक दामोदर सावरकर का राष्ट्रप्रेम जागा और उन्होंने नहले का जवाब दहले से देने के लिए वहां रह रहे हिंदुस्तानी नौजवानों व छात्रों को 'अभिनव भारत' के बैनर पर संगठित करके '1857 के शहीदों की इज्जत और लोगों को उसका सच्चा हाल बताने के लिए' अभियान शुरू किया. 1909 में उन्होंने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'दि हिस्ट्री ऑफ इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस' लिखी, जिसमें 1857 को 'भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम' बताया तो उसे जब्त कर लिया गया.

दुर्भाग्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस जब्ती के खिलाफ मुंह तक नहीं खोला. आगे उसने अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर क्रांतिकारियों के 'हिंसक संघर्षों' की आलोचना भी की. तब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन व नौजवान भारत सभा के प्रख्यात क्रांतिकारी भगवतीचरण बोहरा ने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह से सलाह-मशविरा करके 'बम का दर्शन' लिखा था.

अप्रैल, 1928 में उन्होंने 'किरती' में 'दस मई का शुभ दिन' शीर्षक से एक लेख में 1857 की बाबत लिखा था- भारतवासियों द्वारा अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का यह प्रथम प्रयास था, जो भारत के दुर्भाग्य से सफल नहीं हुआ. इसलिए हमारे दुश्मन इस 'आजादी की जंग' को गदर और बगावत के नाम से याद करते हैं और इसके नायकों को कई तरह की गालियां देते हैं. विश्व के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां ऐसी जंगों को इसलिए कई बुरे शब्दों में याद किया जाता है कि वे जीती नहीं जा सकीं. आज दुनिया गैरीबाल्डी और वाशिंगटन की बड़ाई व इज्जत करती है क्योंकि उन्होंने आजादी की जंग लड़ी और उसमें सफल हुए.

इसी लेख में उन्होंने आगे लिखा है कि 1907 में सावरकर ने दस मई को भारत के राष्ट्रीय त्यौहार में बदल दिया. यह बड़ी बहादुरी का काम था जो अंग्रेजी राजधानी लंदन में किया गया. 'हिंदुस्तानी घर' में एक बड़ी यादगारी मीटिंग बुलाई गई, उपवास किए गए और कसमें ली गईं कि एक हफ्ते तक विलासिता की कोई चीज इस्तेमाल नहीं की जाएगी. बाद में अभिनव भारत सोसायटी टूट गई और इंग्लैंड में दस मई का त्यौहार मनाए जाने का सिलसिला टूट गया. इसकी क्षतिपूर्ति यों हुई कि अमेरिका में हिंदुस्तान गदर पार्टी बनी और उसने वहां हर साल इसे मनाना शुरू कर दिया.

आज, जब 1857 के डेढ़ सौ साल पूरे होने के अवसर पर हुए रस्मी आयोजन भी पुराने पड़ गए हैं, जरूरत है कि उस दस मई की यादों को धुंधलाने न दिया जाए. वह एक ऐसी तारीख है, जिसकी याद हमें भविष्य की लड़ाइयों के लिए बल देती है. ■■

प्रतिभा को कोई बाधा रोक नहीं सकती

स्मार्ट स्ट्रीट
बिजनेसमैन

प्रकाश बियाणी
कॉर्पोरेट इतिहासकार

हमारे देश के राजनेता, समाजसेवी ही नहीं, शिक्षाविद तक अक्सर कहते हैं कि पुरुष-महिला एक-दूसरे के पूरक हैं. दोनों को समान शिक्षा, समान अवसर व समान अधिकार मिलना चाहिए. ऐसी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर इसमें एक ध्वनि छुपी हुई है- 'महिलाएं पुरुषों के बराबर हो सकती हैं, बेहतर या अव्वल नहीं.' सच्चाई यह है कि प्रतिभा केवल प्रतिभा होती है, पुरुष या महिला नहीं. प्रतिभा को मौका मिले तो उसकी उन्नति में जेंडर बाधा नहीं बनता. इसकी मिसाल हैं डॉ. रेणु खटोड़ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं, पर यह भी उनके व्यक्तित्व व उनकी उपलब्धि का एक अंश मात्र है.

डॉ. रेणु खटोड़

हर भारतीय महिला के लिए गर्व की बात है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड और प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से विभूषित डॉ. रेणु खटोड़ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ डेलास (टेक्सास, उत्तरी लुसियाना व सदर्न न्यू मैक्सिको की रीजनल रिजर्व बैंक) की चेयरपर्सन नियुक्त की गई हैं. 66 हजार छात्रों एवं 1.3 बिलियन डॉलर (करीब 62 अरब रुपए) बजट वाले युनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन सिस्टम की चांसलर एवं युनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन की प्रेसीडेंट डा. रेणु खटोड़ के अनुसार उन्हें शिखर पर पहुंचाने वाले शख्स हैं उनके पति डॉ. सुरेश खटोड़, जिन्होंने विवाह के बाद उनसे कहा था- ''भूल जाओ कि किसी की बेटी हो या मेरी पत्नी. तुम सबसे पहले जो हो, उसे खोजो.''

फर्रुखाबाद (यूपी) में 29 जून 1955 को जन्मी रेणु खटोड़ के मां-पिता महिला शिक्षा के पक्षधर थे, पर सुरक्षित माहौल में. रेणु ने मिशनरी स्कूल में 8वीं तक और इसके बाद एक हिंदू गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई की. ग्रेजुएशन डिग्री उन्होंने ऐसी रैंक से प्राप्त की कि उन्हें फेलोशिप मिल गई. पर पिता विदेश ही नहीं, दूसरे शहर भी भेजने को तैयार नहीं थे. अंकल के पैरवी करने पर उन्हें इलाहाबाद में पढ़ने की अनुमति मिली. पर 11 माह बाद ही घर से बुलावा आ गया. पिता ने उनका विवाह तय कर दिया था. विवाह के बाद पढ़ाई को विराम लग जाएगा- इस डर से रेणु ने विरोध किया, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी. 18 वर्ष की उम्र में विवाहित रेणु अमेरिका आ गईं, जहां उनके पति पीएचडी कर रहे थे.

रेणु को अमेरिका तो रास आया, पर वे कामचलाऊ अंग्रेजी ही बोल पाती थीं. अमेरिकन उच्चारण की अंग्रेजी उन्हें समझ नहीं आती थी. पुरड्यू युनिवर्सिटी में प्रवेश के साक्षात्कार में डॉ. सुरेश खटोड़ उनके अनुवादक बने. रेणु को वहां नॉन-डिग्री स्टूडेंट के रूप में प्रवेश मिला यानी पहले सिद्ध करो कि ग्रेजुएशन कोर्स के योग्य हो? परड्यू युनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए डॉ. सुरेश खटोड़ ने रेणु को अंग्रेजी में पारंगत किया तो टीवी टॉक शो देखकर उन्होंने अमेरिकन उच्चारण वाली अंग्रेजी समझी. 1975 में राजनीति विज्ञान की मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद रेणु पीएचडी करना चाहती थीं, पर स्वदेश लौटना पड़ा. डॉ. सुरेश इस शर्त के साथ छात्रवृत्ति लेकर अमेरिका गए थे कि स्टडी पूरी होने पर देश लौटेंगे. 1976 में खटोड़ दंपति भारत लौट आए. यहां वे दो पुत्रियों के मां-पिता बने. उनकी बेटियां पूजा व पारुल दोनों आज नेत्ररोग विशेषज्ञ हैं.

अपने पीएचडी गाइड के बुलावे पर डॉ. सुरेश पांच साल बाद अमेरिका लौटे. यहां सन् 1985 में पॉलिटिकल साइंस व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रेणु खटोड़ ने डॉक्टरेट प्राप्त की. इसके बाद युनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में अध्यापन करते हुए युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी प्रतिभा व योगदान के कारण वहां सीनियर वाइस प्रेसीडेंट बन गईं.

2004 में उन्हें मोस्ट पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर का सम्मान मिला. सन 2008 में उनकी प्रतिभा को सही मुकाम मिला. वे पहली विदेशी शिक्षाविद और दूसरी महिला हैं, जिन्हें ह्यूस्टन युनिवर्सिटी के दो सिरमौर पद प्रदान किए गए हैं. ■■

तोल बोल

यदि आपको अच्छी सेवाएं चाहिए तो इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा. टोल खत्म नहीं होगा, लेकिन सरकार उसमें कुछ राहत देने के उपाय ढूंढ़ रही है.
■ **नितिन गडकरी**, केंद्रीय मंत्री

भ्रष्टाचार अब खून में ही नहीं, हड्डियों में तक चला गया है और गरीब के पास योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है.
■ **शरद यादव**, जद(यू) अध्यक्ष

पाठकों के पत्र

वापस नहीं आएगा काला धन!

विदेशों से काला धन वापस लाने की बात एक सपना है जिसके लिए आगे पीछे लीपा-पोती की जाएगी. तो फिर क्या काला धन नहीं ला पाने का दोष इस सरकार को दिया जाएगा? जैसे-जैसे समय बीतेगा, परिणाम न के बराबर होगा. वैसे काला धन रखने के लिए केवल स्विट्जरलैंड ही नहीं बल्कि विश्व में करीब 40-50 ऐसे देश हैं जो खाता धारकों के लिए सुविधाजनक होते हैं. इन्हें 'टैक्स हैवंस' देश भी कहते हैं. इन सभी देशों से संपर्क कर सरकार को जानकारी जुटाना चाहिए. दुःख होता है जब चुनावों में काला धन का आंकड़ा बताने वाले, सौ दिन में 15-15 लाख रुपए देने का वादा करने वाले नेता अब कहते हैं कि ''मुझे तो पता ही नहीं कितना पैसा है और कहां है?'' शायद चुनाव में सब पता था और याद था, अब स्मरणशक्ति ने जवाब दे दिया है. वैसे भी यह दोष वादा करने वालों का नहीं, मतदाता का है जो पिछले अनेक वर्षों से झूठे वादों पर विश्वास करता आ रहा है. ■ **बी. जे. अग्रवाल**, नागपुर

इतिहास पर नजर 10 मई

आज ही के दिन 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे. दक्षिण अफ्रीका में तीन शताब्दियों से गोरे लोगों का राज था. 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए. राजधानी प्रिटोरिया में आज के दिन हुए समारोह में अफ्रीकी राजनेताओं के अलावा 140 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. समारोह में नेल्सन मंडेला ने कहा, 'इस खूबसूरत धरती पर फिर कभी किसी एक के हाथों दूसरे का दमन नहीं किया जाएगा.' ■■

- ■1503-कोलंबस ने कायमान द्वीप की खोज की.
- ■1534-फ्रांसीसी नाविक जैक्स कॉर्टियर न्यूफाउंडलैंड पहुंचा.
- ■1655-अंग्रेजों ने जमैका पर कब्जा किया.
- ■1796-नेपोलियन ने लोदी ब्रिज के युद्ध में आस्ट्रिया को हराया.
- ■1916-एम्स्टरडम में ऐतिहासिक शिपपोर्ट संग्रहालय खोला गया.
- ■1981-पहली बार बॉम्बे (वर्तमान मुंबई) में रात में क्रिकेट मैच खेला गया.
- ■1993-संतोष यादव दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर एवरेस्ट पर दो बार पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही बनीं.

gñWmnH$ gnmXH$: nd. Odmhabmb XS>m
M`a_Z, E[S>Q>m{a`b ~moS>© : {dO` XS>m
E{S>Q>a-BZ-Mr\$: amOoÐ XS>m
gnmXH : {dH$mg {_l★
★ nr. Ama. ~r. H$mZy H$ AZgma gnU gnmXH$s` Xm{`Ëd H$ {bE {OåX_Xma.
© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r gm_J«r H$m gdm©{YH$ma bmoH$_V _r{S>`m àm`ìhoQ> {b. H$ nmg gwa{jV h.
bmoH$_V _r{S>`m àm`ìhoQ> {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam bmoH$_V _r{S>`m àm. {b., ßbmQ> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. Sr. gr. BÝS>{ñQ´>`b E[a`m, ~wQ>r~moar, ZmJnya _{ÐV Ed bmoH$_V ^dZ n. OdmhabmbZhê$ _mJ, ZmJna _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBÝg) \¡$Šg : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com